



भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1980/अष्टावृ 7, 1902

No. 273] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1980/ASADHA 7, 1902

इस भाग में भिन्न घृण संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paginig is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

एस. संग्रालय

प्राधिकार

नई दिल्ली, 28 जून, 1980

का. आ. 422(क).—वांशदीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित
में ऐसा अधिकार है कि खाद्य पदार्थों सम्बन्धी उद्योग में नगो भारतीय खाद्य
नियम को, जिसे औद्योगिक विद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की प्रथम
अनुमति ग्रहन किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए
उपर्याप्त सेवा विधिवत किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की
धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (c) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, कन्द्रीय सरकार भारतीय साइं निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस.-11017/6/80-डी. 1 ए.]

कृ. म. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1980

S.O. 474(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Food Corporation of India engaged in the foodstuffs industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the Food Corporation of India to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/6/80-D.I.A.]

(Miss) M. SETH, Jt. Secy.